

**Uniform Standard of Education at  
School and College Level**

1886. SHRI VISHWA BANDHU  
GUPTA;

SHRI BHAGATRAM  
MANHAR;

SHRI KAMALENDU  
BHATTACHARJEE;

SHRI GHULAM RASOOL  
KAR;

Will the Minister of EDUCATION  
AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to bring uniformity in the standard of education at the school and college level throughout the country;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRIES OF EDUCATION AND  
CULTURE AND SOCIAL WELFARE  
(SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to  
(c) The educational system in India is based on the National Policy on Education which was adopted in 1968.

The policy lays emphasis on the need for uniformity in the educational pattern, adoption of a common curriculum for the 10<sup>th</sup> school pattern and vocationalisation of education at the plus two stage.

The 10+2<sup>nd</sup> pattern of education, has been adopted, by and large, in most of the states. NCERT has prepared a framework for the 10-year school curriculum which has been commended to the State Governments and forms the basis of uniformity in the syllabus all over the country.

At the University level, the UGC's Scheme of restructuring under-graduate courses seeks to introduce some application-oriented components in the first degree courses to ensure skill development and, through it, to improve employability of graduates.

गुजरात के कुछ जिलों को "उद्योग रहित जिले" घोषित करने की मांग

1887. श्री मीर्जा इशदिबेग ऐयूबबेग :  
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पंच महल, अमरेली, बनासकांठा, साबरकांठा और गांधी नगर जिलों को "उद्योग रहित जिलों" की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार विकेन्द्रीयकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

॥ उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने अनुरोध किया था कि अमरेली, बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर और डांगस को उद्योग रहित जिलों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए चूंकि केवल डांगस ही मानदण्ड को पूरा करता है इसलिए, इसे सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। पंचमहल को उद्योग रहित जिलों की सूची में सम्मिलित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।